territory by Nepal has been taken up by Government with the Nepalese authorities ;

(b) what is the outcome thereof; and

(c) in what manner Government propose to get back the encroached Indian territory from Nepalese occupation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA) : (a) to (c) The issue of encroachment of Indian territory by Nepal has been taken up at the level of the Minister of External Affairs with the Nepalese authorities. The Joint Technical Level India-Nepal Boundary Committee which was constituted in 1981 to demarcate finally the India-Nepal boundary along its entire length, has also discussed the matter a number of times in the past.

While the Joint Technical Level Boundary Committee is working hard to complete the demarcation on the basis of accepted principles, there are certain sectors in India-Nepal boundary where there is no agreement regarding these principles. Detailed surveys investigations of the areas involved are proposed to be carried out in consultation with concerned State Governments of India. Senior survey officials of India and Nepal are expected to meet in New Delhi in March. 1994 to discuss all matters relating to demarcation of India Nepal boundary.

Threats of Kidnapping to Indian Diplomats

1054. SHRI S. S. AHLUWALIA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian diplomasts in UK and elsewherer have received threats of kidnapping from separatists in the recent past ;

(b) If so, what are the details thereof; and

(c) what security arrangements have been made by the respective Governments for the safety of the Indian diplomats serving abroad ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA) : (a) No, Sir.

(b) Not applicable.

(c) The security of our diplomats their families and all our missions abroad is primarily the responsibility of the host Government. The security arrangements made depend upon the security environment and the threat perception of the host security services.

We augment these security arrangements by deploying India based Security Guards and installing various types of security equipment These security arrangements are periodically reviewed and suitably augmented in cooperation with the host Government.

Extradtion Treaty with Nepal

1055. SHRI S. S. AHLUWALIA : Will the Minister OF EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whethe Government propose to sign extradition treaty with Nepal to check terrorism and prevent criminals taking shelter in Nepal after committing heinous crimes on the Indian soil

(b) if so, what are the details thereof ; and

(c) what is the reaction of the Nepalese Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTRNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA) : (a) and (b) The Government of India entered into a Treaty of Extradition with Government of Nepal on October 2, 1953. Under the Treaty the two Governments engage to deliver up to each other those persons accused or convicted of a crime in the territory of one Government who are found within the territory of the other Government, in circumttances provided in the Treaty Extradition under the Treaty may be granted for murder, dacoity and other major crimes.

(c) Does not arise.

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् को दी गई धनराशि

1056. श्री ईश दत्त यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय

सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् को अनुदान के रूप में धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि दी गयी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन संस्थाओं की समय-समय पर समीक्षा और आकलन प्रभावी ढंग से नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश **मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया)** : (क) और (ख) जी, हां। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् को नीचे लिखे अनुसार अनुदान दिए गए :

वर्ष	राशि (लाखों में)
1989-90 . . .	968.00
1990-91 . .	1209.00
1991-92 . .	1350.00
1992-93 . . .	1455.00
1993-94 . . .	1500.00

(ग) और (घ) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद की गतिविधियों तथा उसके कार्यक्रमों की परिषद के 3 सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निरन्तर निरीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाता है। परिषद के ये तीन प्राधिकरण हैं—महासभा, शासी निकाय और वित्त समिति। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के संविधान के अन्तर्गत यह शासी निकाय विशेष रूप से परिषद के कार्य के निरीक्षण तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त विदेश सचिव भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के पदेन उपाध्यक्ष हैं। विदेश मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार परिषद के भी वित्तीय सलाहकार हैं। इन सबसे यह सुनिश्चित किया जाता है कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद की गतिविधियों तथा कार्यक्रम परिषद को प्रदत्त आदेश की रूपरेखा के अन्तर्गत किए जाते हैं।

विदेशों में सांस्कृतिक केन्द्र

1057. श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा किन-किन देशों में सांस्कृतिक केन्द्र चलाये जा रहे हैं;

(ख) उक्त सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा किये गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अन्य देशों में भी सांस्कृतिक केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के आठ केन्द्र हैं जो जार्जटाउन (गयाना), जकार्ता (इन्डोनेशिया), मास्को (रूस), पोर्ट लुई (मारीशस), पारामारिबो (सूरीनाम), काहिरा (मिस्र), बर्लिन (जर्मन संघीय गणराज्य), लंदन (यू० के०) में स्थित हैं जिनका काम भारत की सांस्कृतिक विरासत के संबंध में अधिकाधिक जानकारी बढ़ाना और भारत की समकालीन गतिविधियों के संबंध में सूचना प्रदान करना है। ये केन्द्र भारत के विभिन्न पहलुओं पर भाषण, व्याख्यान, फिल्म-प्रदर्शनियां जैसे नियमित कार्यकलाप आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ केन्द्र भारतीय संगीत, नृत्य, योग और हिन्दी की नियमित कक्षाएं भी आयोजित करते है। ये केन्द्र पुस्तकालय एवं वाचनालय का भी अनुरक्षण करते हैं। ये केन्द्र जहां उपयुक्त होता है, विदेशों में बसे भारतीय मूल क लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यकलाप विकसित करते हैं।